

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,  
रुद्रप्रयाग।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 1 <sup>जुलाई</sup> जून, 2008

**विषय:-** एल0 एण्ड टी0 उत्तरांचल हाइड्रोपॉवर लि0 को सिंगोली भटवाड़ी हाइड्रोइलेक्ट्रिकल्स प्रोजेक्ट हेतु जनपद रुद्रप्रयाग में कुल 9.027 है0 भूमि क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-555/7-1(2004-2005) दिनांक 16 नवम्बर, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल हाइड्रोपॉवर लि0 को सिंगोली भटवाड़ी हाइड्रोइलेक्ट्रिकल्स प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग, की तहसील ऊखीमठ के ग्राम बष्ठी, जलई सुरसाल, सेमी तल्ली फलई तड़ियाल एवं हाट तथा तहसील जखोली के ग्राम रायड़ी तथा अरखुण्ड में कुल 9.027 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये (हाइड्रोइलेक्ट्रिकल्स प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु) करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये

24

विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी एवं भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 180 दिन के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा। निर्माण कार्य राज्य द्वारा अनुमोदित डी0पी0आर0 के अनुरूप किया जायेगा।

7- स्थापित किये जाने वाली परियोजना में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

8- किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग कोई भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जायेगा।

9- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

10- योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/अनापत्तियां/स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जायेगी।

11- उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)


प्रमुख सचिव।

.....(3)

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- श्री हरीन बुच, प्रोजेक्ट मोनेजर, सिंगोली भटवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्टन0-06, ग्राम गवनी, निकट जलागम ऑफिस, चन्द्र पुरी, जिला रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड।
- 5- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा, से,  
  
(सन्तोष बडोनी)  
अनुसचिव।